वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को देश का आम बजट पेश किया. यह मोदी 3-0 का पहला और उनका रिकॉर्ड 7वां बजट था. वह लगातार 7 बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन गई हैं. उन्होंने मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ा है. इस दौरान वित्त मंत्री ने कई घोषणाएं भी कीं. घोषणाएं होते ही पक्ष के लोगों ने वाह-वाह किया है. वहीं विपक्ष ने इसे जनता से बहुत दूर का बजट करार दिया है.

न्यू टैक्स रिजीम में राहत

17500 तक का सीधा फायदा » **ओल्ड टैक्स रिजीम वाले घाटे में**

किसानों के लिए खोला खजाना, 1.52 लाख करोड़ रुपये आवंटित

लगातार न्यूज नेटवर्क । मोदी 3-0 सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में कृषि और किसानों के लिए खजाना खोल दिया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल के बजट में किसानों का खास ध्यान रखा है और किसानों की कमाई में इजाफा करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं. बजट में किसानों और कृषि क्षेत्र के 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. इस फंड से कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी. इस दौरान निर्मला सीतारमण के पिटारे से किसानों के लिए कई योजनाएं निकली हैं. बजट 2024 में केंद्रीय सरकार का फोकस कृषि के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, कृषि में तकनीक को बढ़ावा देने और प्राकृतिक खेती की ओर किसानों का रुझान बढ़ाने पर रहा है. हालांकि, बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी और एमएसपी को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है.

कृषि क्षेत्र

किसानों के लिए खुला सरकार का पिटारा

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) : देश के 400 जिलों में डीपीआई का उपयोग करते हुए खरीफ फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण किया जाएगा. पांच राज्यों में जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे. झींगा मछली ब्रूडस्टॉक के लिए केन्द्रीकृत प्रजनन केंद्रों का नेटवर्क स्थापित करने हेतु वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा. ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वृद्धि और रोजगार सृजन में तेजी लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सहयोग नीति तैयार की जाएगी. किसानों के लिए 32 कृषि और बागवानी में फसलों की 109 उच्च-पैदावार और जलवायु-अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी. क्रियान्वयन में सहायता के लिए 10 हजार आवश्यकता आधारित जैव-इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे. देश भर में 1 करोड़ किसानों को प्रमाणीकरण और ब्रांडिंग के माध्यम से प्राकृतिक खेती की शुरुआत की जाएगी.

घर-परिवार

बच्चों के लिए ऐसे करें बचत, मिलेगा फायदा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में 'एनपीएस-वात्सल्य' योजना की भी घोषणा की है. वित्त मंत्री ने कहा, 'एनपीएस-वात्सल्य के रूप में नाबालिग बच्चों के लिए माता-पिता और अभिभावकों द्वारा योगदान की एक योजना शुरू की जाएगी. नाबालिग के वयस्क होने पर योजना को निर्बाध रूप से सामान्य एनपीएस खाते में परिवर्तित किया जा सकता है. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस), केंद्र सेवानिवृत्त होने के बाद भी एक निश्चित आमदनी आपके खाते में आती है. इस योजना के तहत आपको लंबी अवधि तक निवेश करना होता है. अब आप इस योजना के तहत अपने नाबालिग बच्चों के नाम पर भी निवेश कर सकेंगे. केंद्र सरकार ने इस अतिरिक्त योजना को 'एनपीएस-वात्सल्य' नाम दिया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एनपीएस-वात्सल्य योजना के तहत माता-पिता अपने नाबालिग बच्चे के नाम पर निवेश कर सकेंगे.

गरीब-मध्यम वर्ग

एक करोड़ परिवारों को घर, मिलेगी सब्सिडी

बजट भाषण में वित्त मंत्री ने एलान किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में तीन करोड़ अतिरिक्त घरों की घोषणा की गई है. इसके लिए आवश्यक आवंटन किया गया है. औद्योगिक श्रमिकों के लिए छात्रावास शैली के आवासों के साथ किराये के आवास बनाए जाएंगे. इसे सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी मोड) के माध्यम से किया जाएगा. बजट में पीएम आवास योजना (शहरी) 2.0 का प्रस्ताव किया गया है. इसके तहत 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से एक करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की आवास की जरूरत को पूरा किया जाएगा. इसमें अगले पांच वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता शामिल होगी. शहरी आवास के लिए किफायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए सरकार ब्याज सब्सिडी योजना लाएगी. इसके साथ ही सरकार बेहतर उपलब्धता के साथ कुशल और पारदर्शी किराये के आवास बाजार की स्थापना करेगी.

मध्यम वर्ग के लिए राहत

पारिवारिक पेंशन पर बढ़ी छूट की सीमा

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की जाएगी, जिससे टैक्स संबंधी विवाद और मुकदमेबाजी कम होगी. इसे 6 महीने में पूरा करने का प्रस्ताव है. नई कर व्यवस्था में व्यक्तिगत आयकर दरों पर वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, 'नई कर व्यवस्था के तहत, कर दर संरचना ऐसी होगी, जिसमें 0 से 3 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगेगा. 3-7 लाख रुपये की आय पर 5% और 7-10 लाख रुपये की आय पर 10% आयकर लगेगा. वहीं 10-12 लाख की आय पर 15% और 12-15 लाख रुपये की सालाना आय पर 20%, और 15 लाख से अधिक की आय पर 30% आयकर लगेगा. सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया है. पारिवारिक पेंशन पर छूट की सीमा 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये की जा रही है. वित्त मंत्री ने कहा कि इन दोनों बदलावों से चार करोड़ नौकरीपेशा और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा. वित्त मंत्री ने कहा कि केवल उन मामलों में आयकर आकलन को 3 साल बाद फिर से खोला जाएगा, जहां बंदी हुई आय 50 लाख रुपये और उससे अधिक है. वित्त मंत्री ने कहा कि दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर को 10 से बढ़ाकर 12.5% किया गया और दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ छूट 1 लाख से बढ़ाकर 1.25 लाख किया गया.

मोबाइल- दवाइयां सस्ती

वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि मोबाइल फोन और उपकरणों के घरेलू उत्पादन में इजाफा हुआ है. मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर पर सीमा शुल्क घटाया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा मोबाइल फोन और मोबाइल पीसीबीएस तथा मोबाइल चार्जर पर बीसीडी को घटाकर 15% करने का प्रस्ताव करती हूं. इसके चलते देश में मोबाइल और मोबाइल उपकरण सस्ते होंगे. वित्त मंत्री ने कहा, 'प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक निशुल्क बिजली मिल सकेगी. यह योजना इसे और बढ़ावा देगी. बजट के दौरान वित्तमंत्री ने कैंसर रोगियों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने कैंसर की तीन दवाओं के कस्टम ड्यूटी हटाने का प्लान किया है. कैंसर की कुछ दवाएं और कैंसर के उपचार में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण सस्ते होंगे. इससे रोगियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है. गौरतलब है कि कैंसर की समस्या तेजी से बढ़ती जा रही है और इसका उपचार प्राप्त करना और दवाओं पर खर्च आम आदमी की जेब पर बड़ा भार डालता है. वित्त मंत्री निर्मला ने चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम के तहत मेडिकल एक्स-रे मशीनों में उपयोग के लिए एक्स-रे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिटेक्टरों पर आयात शुल्क हटाने की घोषणा की है. कैंसर के मरीजों के लिए तीन और दवाओं को पूरी तरह सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया जाएगा. एक्सरे ट्यूब, फ्लैट पैनल डिटेक्टर में भी सीमा शुल्क घटाया जाएगा. सोने और चांदी पर सीमा शुल्क छह फीसदी और प्लेटिनम पर 6.4 फीसदी सीमा शुल्क घटाया जाएगा. एक करोड़ परिवारों को हर महीने मिलेगी 300 यूनिट मुफ्त बिजली.

इन्फ्रास्ट्रक्चर

औद्योगिक केंद्र का विकास किया जाएगा

अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे के तहत गया में औद्योगिक केंद्र का विकास किया जाएगा. 26 हजार करोड़ रुपए की कुल लागत से इन सड़क संपर्क परियोजनाओं का विकास किया जाएगा. पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस-वे, बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस-वे बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा में सड़कों के काम में तेजी लाई जाएगी. बक्सर में गंगा नदी पर नया 2-लेन वाला एक पुल बनेगा.

उद्योग

खनिज मिशन शुरू किया जाएगा

100 शहरों में या उसके आसपास निवेश के लिए प्लग एंड प्ले' औद्योगिक पार्कों का निर्माण किया जाएगा. राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी जाएगी. खनिजों के घरेलू उत्पादन, रिसाइक्लिंग और विदेश में महत्वपूर्ण खनिज आस्तियों का अधिग्रहण करने के लिए महत्वपूर्ण खनिज मिशन शुरू किया जाएगा.

शहरी विकास

पीपीपी मोड पर मकानों का निर्माण होगा

आर्थिक और आवागमन योजना के जरिए बाह्य शहरी क्षेत्रों का सुनियोजित विकास, मौजूदा शहरों के रचनात्मक ब्राउनफील्ड पुनर्विकास के लिए रूपरेखा. 100 बड़े शहरों के लिए जलापूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट और ठोस कचरे का प्रबंधन परियोजनाएं एवं सेवाएं. 30 लाख से ज्यादा आबादी वाले 14 बड़े शहरों के लिए आवागमन संबंधी विकास योजनाएं. पीएम आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत एक करोड़ शहरी गरीब व मध्यमवर्गीय परिवारों को लाभ मिलेगा. चयनित शहरों में 100 हाट या स्ट्रीट फूड हब बनेंगे. औद्योगिक कर्मियों के लिए पीपीपी मोड में किराए के मकानों का निर्माण किया जाएगा.

ऊर्जा सुरक्षा

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना चालू

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1.28 करोड़ से ज्यादा पंजीकरण किए गए और 14 लाख आवेदन प्राप्त हुए. विद्युत भंडारण और समग्र ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा के निर्बाध एकीकरण के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए पम्पड स्टोरेज परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति लाई जाएगी. परमाणु ऊर्जा के लिए नई प्रौद्योगिकियों और स्मॉल और मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टर का अनुसंधान और विकास. उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर (एएएससी) प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से एनटीपीसी और बीएचईएल का एक संयुक्त उद्यम 800 मेगावाट का वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित करेगा. हार्ट टू पेक्ट उद्योगों के लिए रोडमैप तैयार किया जाएगा. 60 क्लस्टरों में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की निशा ग्रेड ऊर्जा लेखा परीक्षा की सुविधा से स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी.

ऋण-रोजगार

मुद्रा योजना में मिलेगा 20 लाख तक ऋण

देश में चलने वाली कई तरह की योजनाओं के जरिए गरीब और मध्यम वर्ग को लोन दिया जाता है. इसके लिए भारत सरकार कई तरह की योजनाएं चलाती है जिसमें से एक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना. इसी योजना को लेकर वित्त मंत्री ने संसद में बजट पेश करने के दौरान मुद्रा लोन को लेकर एक बड़ा एलान किया. तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि ये ऐलान किया है और किन्हें इसका लाभ मिल सकेगा. दरअसल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि अब मुद्रा लोन 20 लाख रुपए तक मिल सकेगा. जबकि इससे पहले ये लोन सीम 10 लाख रुपए तक की थी. ऐसे में इस घोषणा से मुद्रा लोन लेने वाले लोगों को सीधे तौर पर लाभ मिल सकता है. सरकार ने इस योजना की शुरुआत साल 2015 में की थी.

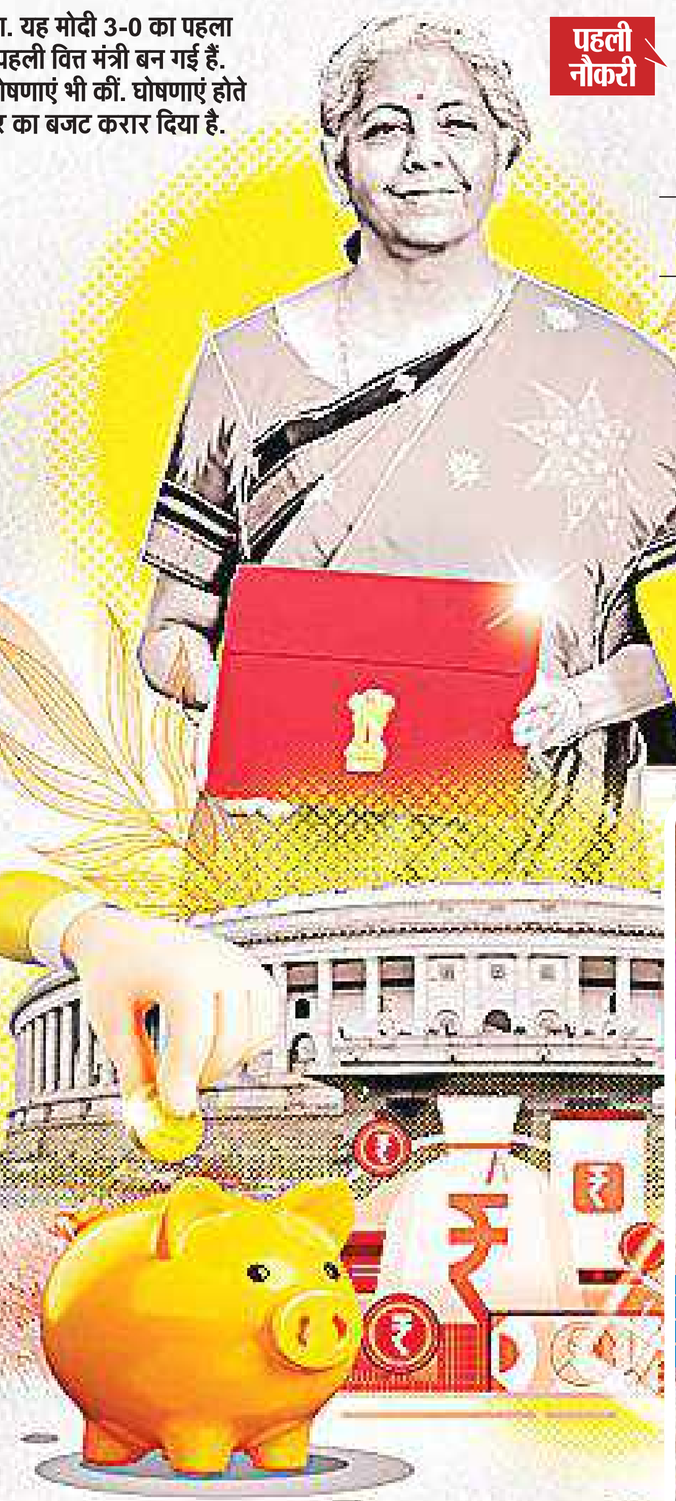

सोने का भाव करीब 4000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक घट गया

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है और इसमें सोना-चांदी को लेकर एक बड़ा ऐलान किया गया है. इसके बाद सोने की कीमतों में अचानक बड़ी गिरावट देखने को मिली है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण खत्म होते-होते सोने का भाव करीब 4000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक घट गया. एमसीएक्स पर यही पहुंचा भाव वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में सोने और चांदी समेत अन्य मेटल्स पर कस्टम ड्यूटू घटाने का ऐलान किया है. सरकार ने सोना और चांदी पर पहले से लागू कस्टम ड्यूटी कम करके अब 6% कर दिया है.

पहली नौकरी

सीधे खाते में आएंगे 15 हजार, पीएफ भी सरकार देगी, 2.1 करोड़ युवाओं के लिए बड़ा ऐलान : वित्त मंत्री ने पहली बार नौकरी पाने वालों को तोहफा दिया है. सीतारमण ने कहा कि संगठित क्षेत्र में पहली बार नौकरी की शुरुआत करने वालों को एक महीने का वेतन दिया जाएगा. यह वेतन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के जरिए तीन किस्तों में जारी होगा.

1. पहली बार नौकरी पाने वालों को तोहफा : सीतारमण ने कहा, रोजगार और कौशल विकास सरकार की नौ प्राथमिकताओं में से एक है. इसके तहत पहली बार नौकरी करने वालों को बड़ी मदद मिलने जा रही है. संगठित क्षेत्र में पहली बार नौकरी की शुरुआत करने वालों को एक महीने का वेतन दिया जाएगा. यह वेतन डीबीटी के जरिए तीन किस्तों में जारी होगा. इसकी अधिकतम राशि 15 हजार रुपए होगी. ईपीएफओ में पंजीकृत लोगों को यह मदद मिलेगी. योग्यता सीमा एक लाख रुपये प्रति माह होगी. इससे 2.10 करोड़ युवाओं को फायदा होगा.

2. पीएफ में एक महीने का योगदान : वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार रोजगार से जुड़ी तीन योजनाएं शुरू करेगी. उन्होंने कहा कि एक महीने का पीएफ (भविष्य निधि) योगदान प्रदान करके नौकरी बाजार में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं को प्रोत्साहन प्रदान करेगी. उन्होंने घोषणा की कि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए देश में कामकाजी महिला छात्रावास स्थापित किए जाएंगे.

3. एक करोड़ युवाओं को टॉप-500 कंपनियों में 12 महीने इंटर्नशिप और हर महीने भत्ता : वित्त मंत्री निर्मण सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार एक करोड़ युवाओं को अगले पांच साल में टॉप-500 कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका देगी. यह इंटर्नशिप 12 महीने की होगी. इसमें युवाओं को कारोबार के वास्तविक माहौल को जानने और अलग-अलग पेशे की चुनौतियों से रूबरू होने का मौका मिलेगा. इसके तहत युवाओं को हर महीने पांच हजार रुपए का भत्ता भी दिया जाएगा. यही नहीं, उन्हें एकमुश्त मदद के रूप में छह हजार रुपए दिए जाएंगे. कंपनियों को अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत प्रशिक्षण का खर्च और इंटर्नशिप की 10 फीसदी लागत को वहन करना होगा.

4. 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा : उन्होंने कहा, मुझे कौशल विकास और राज्य सरकारों व उद्योग जगत के साथ सहयोग के लिए प्रधानमंत्री पैकेज के तहत चौथी योजना के तौर पर केंद्र की नई प्रस्तावित योजना की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है. पांच साल की अवधि में 20 लाख युवाओं को कुशल बनाया जाएगा. एक हजार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को हब में अपग्रेड किया जाएगा.

5. जलवायु के अनुकूल बीज विकसित करने के लिए धन मुहैया करेगी सरकार : सीतारमण ने कहा कि सरकार जलवायु के अनुकूल बीज विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र और उससे जुड़े विशेषज्ञों व अन्य को धन मुहैया कराएगी.

6. मनरेगा में परिवार के एक सदस्य को कम से कम 100 दिन का रोजगार : उन्होंने आगे कहा, पहले मौजूद मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी) योजना में प्रत्येक उस परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाएगा, जिसके वयस्क सदस्य शारीरिक काम चाहते हैं.

शिक्षा

कौशल विकास और रोजगार पर जोर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 में उच्च शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार प्रोत्साहन को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं. इस बार के केंद्रीय बजट में शिक्षा के क्षेत्र को 1.48 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. यह शिक्षा क्षेत्र के लिए पिछले साल के मुकाबले और अब तक की सबसे अधिक राशि है. इस बार के शिक्षा बजट में आवंटित राशि से शैक्षिक बुनियादी ढांचे में सुधार लाने, नौकरी के अवसर पैदा करने और पूरे देश में कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ाने की उम्मीद है. वहीं, युवाओं को स्किल्ड बनाना के उद्देश्य से पीएम पैकेज के तहत युवाओं के लिए पांच मुख्य स्कीम की घोषणा की गयी है. इसके लिए दो लाख करोड़ रुपये का फंड आवंटित किया गया है. इस बार के बजट में कामकाजी महिलाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया है. इसके अलावा युवाओं के कौशल प्रशिक्षण, आईआईटी संस्थानों के विकास पर भी ध्यान दिया गया है.

रेलवे

इंफ्रास्ट्रक्चर-यात्री सुरक्षा पर जोर

बुजुर्ग रेल यात्रियों को सरकार ने फिर किया निराश : केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से रेलवे को लेकर कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं करने की उम्मीद थी, लेकिन केंद्र ने पूंजीगत व्यय को अंतरिम बजट 2024 में घोषित किए गए अनुसार ही रखा. वित्त मंत्री के बजट भाषण में भारतीय रेलवे का केवल एक बार उल्लेख किया गया, जो उम्मीदों के विपरीत था. इस बजट में रेलवे का फोकस रेल दुर्घटनाओं को कम करने और ढांचागत मजबूती पर रखा गया है. इसके अलावा वंदे भारत, अमृत भारत और बुलेट ट्रेनों पर भी सरकार काम कर रही है. सुरक्षा और यात्री आरामदेह को भी प्राथमिकता दी गई है. हालांकि बुजुर्ग रेल यात्रियों की उम्मीदों पर एक बार फिर पानी फिर गया है. कोरोना काल से बंद बुजुर्गों को रेल टिकट पर मिलने वाली रियायत पर इस बार के बजट में भी कोई चर्चा नहीं है. बुजुर्ग ये मांग बहुत दिनों से कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उन्हें निराश किया है. कुल मिला कर रेलवे को इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा जोर है. साथ ही यात्रियों की सुरक्षा पर धन खर्च करने की बात कही गयी है.

आम बजट पेश करने जाती वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

आइए जानते हैं, रेलवे को क्या-क्या मिला...

नई रेल लाइन बिछाने के लिए 34,603 करोड़ रुपये : मोदी 3.0 सरकार के पहले बजट में नई रेल लाइनों के बिछाने के लिए अनुमानित 34,603 करोड़ रुपये की राशि के आवंटन की योजना है. पिछले आम बजट में यह राशि 34,410 करोड़ रुपये थी. वहीं, दोहरी रेल लाइन बिछाने के लिए बजट की राशि को कम किया गया है. 2024-25 के बजट में अनुमानित 29,312 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि 2023-24 के बजट में 35,046 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे.

रेल यात्रियों की सुविधाओं के लिए 15,511 करोड़ रुपये : इस बजट में रेल यात्रियों की सुविधाओं के लिए 2024-25 के बजट में 15,511 करोड़ रुपये आवंटित करने की योजना है. पिछले बजट में यह राशि 15,18 करोड़ रुपये थी. वहीं, रेलवे की विद्युतीकरण परियोजनाओं के लिए अनुमानित 6472 करोड़ रुपये आवंटित करने की योजना बनाई गई है. यह राशि 2023-24 के केंद्रीय बजट के मुकाबले 1889 करोड़ रुपये कम है. पिछले पूर्ण बजट में यह राशि 8361 करोड़ रुपये थी.

रेलपथ नवीकरण के लिए भी बजट की राशि को बढ़ाया : सिग्नल और दूरसंचार संबंधी कार्यों के लिए भी बजट की राशि बढ़ायी गयी है. इसके लिए इस बजट में 4647 करोड़ रुपये आवंटित करने की योजना है. 2023-24 के आम बजट में यह राशि 3,581 करोड़ रुपये थी. इसी तरह, रेलपथ नवीकरण के लिए भी बजट की राशि बढ़ायी गयी है. इस बजट में इसके लिए 17,652 करोड़ रुपये की राशि आवंटित करने की योजना है. पिछले केंद्रीय बजट में यह राशि 16,826 करोड़ रुपये थी.

जीबीएस मद में 2.52 लाख करोड़ का आवंटन बरकरार : 2024-25 के अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेलवे को संकल बजटीय सहायता (जीबीएस) के रूप में 2,52,200 करोड़ रुपये आवंटित किए थे. बजटीय संसाधनों (इबीआर) से अतिरिक्त 10,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे. बजट 2024-25 में इसे बरकरार रखा गया है. इसके अलावा सरकार की प्राथमिकता सूची में कवच-स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली का दायरा बढ़ाने में तेजी लाना भी शामिल है.

रक्षा मंत्रालय

सेना को 6.21 लाख करोड़ का बजट आवंटन

रक्षा मंत्रालय को कुल बजट का 12.9% और जीडीपी का 2.5% मिलाकेंद्र सरकार ने वर्ष 2024-25 के आम बजट में रक्षा मंत्रालय के लिए अब तक का सर्वाधिक 6,21, 940 करोड़ रुपये का आवंटन किया है, जो कुल बजट का 12.9% है. वहीं, वर्ष 2023-24 में रक्षा मंत्रालय का आवंटन 5,93,537.64 करोड़ रुपये था. रक्षा बजट का आवंटन जीडीपी का लगभग 2.5% है. इस वर्ष के रक्षा बजट में पूंजीगत व्यय के लिए 1.72 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए घरेलू पूंजीगत खरीद के लिए 1,05,518.43 रुपये आवंटित किये गये है. वहीं, सीमा सड़क संगठन के लिए 6500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो पिछले बजट की तुलना में 30 % अधिक है. स्टार्टअप, नवाचार तथा छोटी इकाइयों को प्रौद्योगिकी समावान तथा उन्नयन के लिए आईडेक्स योजना के तहत 518 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. बजट में रक्षा पेंशन मद में 141.205 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

बजट पर नेताओं ने क्या कहा

बजट दूरदर्शी, जनहितैषी व विकासोन्मुखी: अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को संसद में पेश किए गए 2024-25 के आम बजट को दूरदर्शी, जनहितैषी और विकासोन्मुखी करार दिया और कहा कि यह न केवल भारत के उद्देश्य, उम्मीद और आशावाद की नयी भावना का उदाहरण प्रस्तुत करता है बल्कि उन्हें मजबूत भी करता है. शाह ने कहा कि बजट न केवल पीएम के नेतृत्व वाली सरकार के तहत भारत के उद्देश्य, उम्मीद और आशावाद की नयी भावना का उदाहरण देता है.

सशस्त्र बलों को और मजबूत बनाया जाएगा : राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर लिखा, 'भारत सरकार के वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में रक्षा मंत्रालय के लिए सबसे ज्यादा आवंटन किया है. मैं वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने रक्षा मंत्रालय के लिए 6,21,940.85 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. ये कुल बजट का 12.9 फीसदी है. 1,72,000 कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे सशस्त्र बलों की क्षमताओं को और मजबूत करेगा. घरेलू पूंजीगत खरीद के लिए 1,05,518.43 करोड़ रुपये का प्रावधान आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन देगा.

सभी संकल्पों को सिद्ध करने वाला बजट : योगी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को संसद में पेश किये गये केन्द्रीय बजट को 140 करोड़ देशवासियों की आशाओं, आकांक्षाओं और 'अमृत काल' के सभी संकल्पों को सिद्ध करने वाला बजट बताया है. योगी ने 'एक्स' पर अपने संदेश में भी कहा, आम बजट 2024-25 'विकसित भारत-आत्मनिर्भर भारत' के निर्माण का आर्थिक दस्तावेज है. उन्होंने कहा, मध्यम वर्ग को बड़ी राहत प्रदान करते हुए प्रत्यक्ष कर प्रणाली के संबंध में नए प्रावधानों की घोषणा स्वागत योग्य है.

आम बजट से हम बहुत खुश हैं : नीतीश कुमार

आम बजट को लेकर बिहार में सियासी बयानबाजी खूब हो रही है. इस बीच सीएम नीतीश कुमार ने मंगलवार की प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि बजट से हम खुश हैं. विशेष दर्जा के लिए हमलोग आंदोलन कर रहे थे. आज जो बोल रहे हैं जब उनकी पार्टी केंद्र में थी तब क्या किए? हम इसके लिए लगातार बोलते रहे हैं. हमने कहा विशेष राज्य जा दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए मदद कीजिए. हम लोगों ने कह दिया था बिहार को मदद करिए उसी में कई चीजों की मदद की घोषणा हुई है.

बजट लक्ष्य को प्राप्त करने की रूपरेखा : भूपेंद्र पटेल

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मंगलवार को पेश केंद्रीय बजट को 'विकासोन्मुखी' बताते हुए कहा कि इसमें 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की रूपरेखा दी गई है. पटेल ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर कहा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट 2047 तक विकसित भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने की दिशा में एक कदम है. पटेल ने कहा कि यह बजट भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा.

जरूरतों को पहचानने के लिए धन्यवाद : चंद्रबाबू

आंध्र के सीएम ने भी जताई खुशी बजट में आंध्र प्रदेश के लिए की गई घोषणाओं को लेकर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने राज्य की जरूरतों को पहचानने और नई राजधानी अमरावती सहित राज्य में कई विकासों के लिए धन आवंटित करने के लिए केंद्र को धन्यवाद दिया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट 2024 के दौरान आंध्र प्रदेश के विकास के लिए कई उपायों की घोषणा की, जिसमें अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपये की घोषणा भी शामिल है.

पांच साल बाद 'विशेष आवंटन' किया गया : तेदेपा

तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) ने केंद्रीय बजट में पोलावरम परियोजना, औद्योगिक गलियारों और अन्य के लिए घोषित प्रतिबद्धताओं का लिहाज करते हुए मंगलवार को कहा कि पांच साल बाद बजट में आंध्र प्रदेश के लिए विशेष आवंटन किया गया है. आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ तेदेपा ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' के जरिए कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में आंध्र प्रदेश के पुनर्निर्माण के लिए 15,000 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई.

शुभम संदेश
www.lagatar.in
रांची, बुधवार 24 जुलाई, 2024

नकलची व मोदी सरकार बचाओ बजट है : खरगे

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगलवार को आरोप लगाया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की तरक्की वाला नहीं, बल्कि मोदी सरकार बचाओ बजट पेश किया है. उन्होंने यह दावा भी किया कि यह नकलची बजट है जिसमें सरकार कांग्रेस के न्याय के एजेंडे की ठीक तरह से नकल नहीं कर पाई है. खरगे ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, कांग्रेस के न्याय के एजेंडे को ठीक तरह से कॉपी भी नहीं कर पाया मोदी सरकार का "नकलची बजट".

उम्मीद वाला कम, मायूस करने वाला ज्यादा : मायावती

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष मायावती ने मंगलवार को संसद में पेश केंद्रीय बजट को 'अच्छे दिन' की उम्मीदों वाला कम बल्कि उन्हें मायूस करने वाला ज्यादा बताया है. बसपा प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि संसद में पेश केन्द्रीय बजट अपने पुराने दर्रे पर कुछ मुट्ठी भर अमीर व धन्ना सेठों को छोड़कर देश के गरीबों, बेरोजगारों, किसानों, महिलाओं, मेहनतकशों, वंचितों वाला कम बल्कि उन्हें मायूस करने वाला ज्यादा है.

केंद्रीय बजट पक्षपातपूर्ण और गरीब विरोधी : ममता

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2024-25 को 'राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण और गरीब विरोधी' करार दिया और राज्य को (लाभ से) 'वंचित' करने के लिए केंद्र की आलोचना की. मुख्यमंत्री ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल ने ऐसी कौन सी गलती है कि उसे केंद्र ने 'वंचित' कर दिया है. उन्होंने विधानसभा परिसर में संवाददाताओं से कहा, इस केंद्रीय बजट में बंगाल को पूरी तरह से वंचित किया गया है. इसमें गरीबों के हितों का ख्याल नहीं रखा गया है.

दिल्ली को एक पैसा नहीं दिया गया : आतिशी

दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने मंगलवार को कहा कि केंद्र को करों के रूप में 2.32 लाख करोड़ रुपये का भुगतान करने के बावजूद केंद्रीय बजट के केंद्रीय करों में दिल्ली को उसके हि